वोट के लिये अस्मत का सौदा करने वाला धनखड़ है नरेन्द्र मोदी का असली प्रतिनिधि

-मनोज कुमार झा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की फ़ौज में कैसे-कैसे रणबांकुरे भरे हुए हैं, उनके दरबार में कैसे-कैसे नवरतन पल रहे हैं, इसका पता तब चला जब हरियाणा के भाजपा किसान मोर्चा के नेता ओ पी धनखड़ ने 4 जुलाई को जींद के नरवाना में आयोजित किसान महासम्मेलन में निर्लज्जतापूर्वक यह कह दिया कि भाजपा को वोट देने वालों को वे बिहार से लड़कियां लाकर शादी कराएंगे। उन्होंने एक तरह से 'भाजपा को वोट दो, बिहारी दुल्हन पाओ' का नारा ही दे दिया। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में भ्रूणहत्या के कारण लड़कियों की कमी है। इस वजह से युवकों का ब्याह हो पाना काफ़ी कठिन हो गया है। यह देखने में आया है कि भारी संख्या में हरियाणा के शहरी व ग्रामीण इलाके में दूसरे राज्यों से लड़कियों को लाकर लड़को का विवाह कराया जा रहा है। प्राय: लडकियों को खरीद कर लाया जाता है और उन्हें बेचा जाता है, भले ही वेश्या नहीं, एक पत्नी के तौर पर। पर इस स्थिति में जो एक मानवीय विडंबना है, एक त्रासदी है, जो जीवन के मोल को ही खत्म कर देती है, उसे महसूस करने की जरूरत है। स्त्री को एक वस्तु के रूप में, पण्य माल, माल के रूप में देखने की जो वर्णवादी और वाणिज्यवादी दृष्टि है, वह इसके मूल में है। वर्णवादी व्यवस्था ने जहां स्त्री को शूद्र का दर्जा दिया, वहीं वाणिज्यवादी व्यवस्था में उसे माल अथवा कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह के शब्दों में 'टंच माल' का दर्जा दिया गया।

भूलना नहीं होगा कि अब तक के ज्ञात सभ्यता के इतिहास में बड़े पैमाने पर स्त्रियों का व्यापार होता रहा है और आज भी प्रत्यक्ष एवं प्रच्छन्न रूप में यह अपने चरम पर है।

ऐसे में, धनखड़ ने युवक मतदाताओं को बिहारी दुल्हन का लालच दिया, तो इससे कतई ये नहीं कहा जा सकता कि उनके सुसंस्कारों में कहीं कोई कमी है; बल्कि यह अवश्य कहा जा है सकता कि वे परले दर्जे के बेवकूफ हैं कि इतनी सच्ची बात खुले मंच पर हज़ारों लोग़ों के सामने कह दी। मोदी को अपने ऐसे रणबांकुड़ों से थोड़ा सावधान हो जाने की जरूरत है। 'कपट कीजिए, पर गले में कंठी माला डालकर।' मोदी को यह गुरूमंत्र अपने ऐसे सभी दासानुदासों को देना चाहिए, नहीं तो उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी पर रेप का आरोप है ही। वो और भी बदनाम हो जाएंगे। औरतों को उतना कम करके भी न आंके संघ की मानसिकता और संस्कृति कट्टर हिंदूवादी हैं और हिंदूवादी संस्कृति की एक विशिष्टता बलात्कार भी है। सनातन संस्कृति का अनूठा उदाहरण है ये। इस कट्टर हिंदूवादी संस्कृति में यदि स्त्री को देवी मानने का ढोंग किया गया है, वहीं उसे साफ़-साफ 'नरक का द्वार' भी कहा गया है, दूसरी तरफ़ उसे महज भोग का सामान माना गया है। संघ उस ब्रह्मचर्य की धारणा पर चलता है, जिसके तहत 'प्रचारक' का ओहदा पाने के लिए और अपने को कुंआरा घोषित करने के लिये स्वयं मोदी को झूठ बोलना पड़ा था। यह झूठ तब तक छिपा रहा, जब तक कि इसका भंडा फोड़ नहीं हुआ।

कहने का मतलब ये है कि संघ भाजपा नेताओं की धारणा स्त्रियों के प्रति बहुत ही अपमानजनक है और समय-समय पर उनके बयानों से यह जाहिर होता रहा है कि वे स्त्री स्वतंत्रता के सबसे बड़े विरोधियों में हैं। अन्य दलों के कई चरित्र भ्रष्ट और यौन शोषण-बलात्कार आदि के आरोपों से घिरे नेताओं की तरह ही भाजपा-संघ में ऐसे कई नाम हैं जो इस दायरे में आ चुके हैं। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी पर भी गुजरात में एक युवती का पीछा करवाने उसका फोन टैप करने का आरोप है। भूलना नहीं होगा कि इधर हाल के दिनों में विशेषकर, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ में गैंगरेप और हत्या की बाढ सी आ गई है। मोदी सरकार अब तक इस पर कोई नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाई है।

ऐसे में, उनके सिपहसालार धनखड़ का खुल्लेआम ये कहना कि भाजपा को वोट देने वाले को ब्याह करने के लिए लड़कियां बिहार से लाकर दी जाएंगी यह दिखाता है कि ऐसे लोग आगे क्या करनेवालें हैं। सवाल है लड़कियां कैसे दी जाएंगी? भगाकर लाई जाएंगी या खरीद कर? धनखड़ क्या ह्यूमन ट्रैफिक्रिग में शामिल हैं? उसने यह भी कहा कि बिहार के भाजपा नेता सुशील मोदी उसके मित्र हैं। वह उनकी मदद से सस्ते में बिहार से लड़कियां लाकर हरियाणा के कुंआरों की शादी कराएगा। इसका मतलब क्या धनखड़ बिहार से लड़कियों का सौदा करेगा?

उल्लेखनीय है कि हरियाणा, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कई ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो दूसरे राज्यों से लड़कियां लाकर हरियाणवी अथवा अन्य युवकों से उनकी शादी करवाते हैं। सरकार की नाक के नीचे यह जघन्य व्यापार हो रहा है। शादी के अलावा, दिल्ली में कई राज्यों, विशेषकर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, नेपाल और बांग्लादेशी युवतियों का बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा है। इस पर किसी भी सरकार के लिये काबू पा सकना कठिन है, क्योंकि मानव व्यापार में लगे इन गिरोहों की जड़ें बड़ी गहरी और मजबूत हैं। इन्हें सत्ता से संरक्षण हासिल है। इस संरक्षण के बिना इनका अस्तित्व कायम नहीं रह सकता। इसलिए मानव व्यापार करने वाले सभी सरकारों से संरक्षण पाते रहे हैं। पर वे कानून-व्यवस्था की आड़ में अपना धंधा चलाते रहे हैं।

अब मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह नया परिदृश्य सामने आया है कि उनके दासानुदासों में शामिल और विश्वासपात्र धनखड़ खुलेआम वोटरों को बिहारी लड़कियों से शादी कराने का लालच दे रहा है। इस पर हैरत की बात ये भी है कि नीतिश मंत्रिमंडल में बिहार के उपमुख्यमंत्री रह चुके सफेदपोश सुशील मोदी ने उसका बचाव व समर्थन किया है। न तो स्वयं प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के किसी नेता ने धनखड़ को गलत ठहराया है। इससे उसका मनोबल इतना बढ़ गया है कि वह अपने पक्ष में, अपनी बात को जायज ठहराते हुए दलीलें दे रहा है। भूलना नहीं होगा कि हरियाणा में कांडा जैसा नेता भी है, जो अब जेल से बाहर है। यानी औरतों को माल और बलात्कार की वस्तु समझने वाले नेताओं की किसी दल में कोई कमी नहीं है। फिर इन पर लगाम कौन लगाएगा?

धनखड़ ने बिहार की महिलाओं के बारे में जो कुछ कहा है, वह खुली गुंडागर्दी का नमूना है। इसकी कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। खास बात यह है कि धनखड़ महिलाओं का सम्मान करने की झूठी बातें करने वाले मोदी का विश्वस्त व्यक्ति है जिस पर पटेल की लौह प्रतिमा स्थापित करने की महत्त्वकांक्षी योजना का भार है। समझा जा सकता है कि वर्तमान केंद्रीय सरकार में ओछी मानसिकता का यह आदमी कितना अधिक प्रभाव रखता होगा और इसे अपनी ताकत का कितना गुरूर होगा। तभी तो इसे अपने कहे पर जरा भी शर्म और पश्चाताप नहीं।

धनखड़ के इस आपराधिक कुकृत्य का काफ़ी विरोध हुआ है, जो स्वाभाविक ही है। जनता दल (यू) के नेताओं ने इसकी भर्त्सना की है। जदयू अध्यक्ष शरद यादव समेत कई नेताओं ने इसे शर्मनाक बताया है। धनखड़ के खिलाफ़ कार्रवाई की मांग करते हुए बिहार विधानमंडल में हंगामाख़ेज स्थितियां उत्पन्न हुईं। जदयू, कांग्रेस एवं राजद ने 7 जुलाई को दोनों सदनों में इस अजीबो गरीब बात पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिससे सदन की कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ी। वहीं, शर्मनाक बात यह रही कि भाजपा विधायक धनखड़ के पक्ष में खड़े दिखाई पड़े और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने धनखड़ का बचाव तक किया। यानी दो मोदी जब धनखड़ के साथ खड़े हैं तो उसे डरने या शर्माने की जरा भी जरूरत नहीं है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने अपने सुपरिचित अंदाज़ में धनखड़ का कान काट डालने की बात कही।

बहरहाल, इस सबसे होना-जाना कुछ नहीं है। हां, धनखड़ जैसे गुंडा और समाजविरोधी तत्व के सत्ता के उच्चतम सोपान से निकटता ने हरियाणा में बिहारी प्रवासी महिलाओं की इज्जत-आबरू की सुरक्षा को लेकर आशंकाओं के बादल अवश्य मंडराने लगे हैं।

हरियाणा के शहरी, ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में भारी संख्या में प्रवासी बिहारी रहते हैं। और मेहनत-मजूरी कर अपने जीवन की गाड़ी खींचते हैं। इनमें से अधिकांश अत्यंत ही कमजोर वर्ग के हैं झुग्गी-झोपड़ियों में नारकीय जीवन जीने को अभिशप्त हैं। इनकी बहू-बेटियां असुरक्षित हैं और गुंडों के ख़ौफ के साये में जीने को मजबूर हैं। अक्सर गुंडे तत्व इन पर यौन अत्याचार करते रहते हैं। सड़क छाप गुंडों से लेकर बड़े-बड़े सफ़ेदपोश आज लड़कियों-औरतों की तिज़ारत में लगे हुए हैं। यह आधुनिक लोकतंत्रवादी व्यवस्था का घिनौना चेहरा है।

मोदी विकास का जो सपना अभी भी लोग़ों को दिखा रहे हैं, वह विकास तो पहले से ही हो रहा है, अगर और ज्यादा हुआ तो धनखड़ जैसे लोग गरीब राज्यों से मेहनत-मशक्कत कर हरियाणा जैसे तथाकथित अमीर राज्यों में कहीं खुलेआम औरतों की तिज़ारत के लिए मंडियां खोल कर न बैठ जाएं। बहरहाल, धनखड़ ने जो अपराध किया है, उसकी सज़ा अगर नहीं मिलती तो उसका एवं भाजपा-संघ में उसके जैसे लोग जो भरे हुए हैं, उनका मनोबल और भी बढ जाएगा। साथ ही, उनके साथ हरामखोरों की एक जो लंपट फ़ौज है, उससे बहू-बेटियों को बचा पाना गरीबों के लिए मुश्किल हो जाएगा।

ये गुंडे सिर्फ़ प्रवासी मेहनतकशों की बहू बेटियों को ही निशाना नहीं बनाते, अपने राज्य की दलित लड़कियों तक का सामूहिक बलात्कार करते हैं। न जाने कितने उदाहरण हैं। भगाणा कांड सबसे ताज़ा है। खास बात ये है कि धनखड़ जैसे औरतों के दलाल यानी भड़ुवे सभी दलों में हैं। कांग्रेस में भी। यही वजह है कि हुड्डा धनखड़ पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे।

खुलेआम किसी राज्य की महिलाओं के प्रति ऐसे अपमानजनक टिप्पणी करने वालों की तत्काल गिरफ़्तारी होनी चाहिए थी और कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर से कठोर सज़ा दी जानी चाहिए थी। साथ ही, राजनीति से इसका बहिष्कार किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा होगा नहीं। मोदी राज में ऐसे लोग ही आगे बढेंगे।

अब राज्य की जनता को, खासकर प्रवासी बिहारी वोटरों को यह सोचना होगा कि आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या वे भाजपा को वोट देंगे। अगर देंगे तो धनखड़ जैसे लोग उनकी बहू-बेटियों को नीलाम करने के लिये तैयार बैठे हैं। इस धनखड़ के कान लालू क्या काटेंगे, हां प्रवासी बिहारी संगठित हो जाएं तो इसका मुंह काला कर सरे बाज़ार जुलूस निकाल सकते हैं।

मोदी सरकार द्वारा अच्छे दिनों के सपने दिखाकर महंगाई की मार

-जुगल किशोर गुप्ता

लोक सभा के चुनाव प्रचार के दौरान नरेन्द्र मोदी ने यूपीए सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की तथा इन्हीं को महंगाई का मुख्य कारण बताया। मोदी ने लगातार भाषण दिए कि उनके आने से अच्छे दिन आएंगें व आनेवाले दिनों में महंगाई की मार से राहत मिलेगी। अच्छे दिनों की उम्मीद जगातार मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भूमिका बांधते हुए कहा कि ''हमने देश की बागडोर ऐसे समय में संभाली है जब पिछली सरकार ने कुछ नहीं छोड़ा है। वे सब खाली करके गए हैं। राष्ट्रीय हित में कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है। हो सकता है कि कुछ लोग़ों को अभी ये फैसले अच्छे न लगे। कड़वी दवा देने की कड़ी में मोदी सरकार ने यूपीए सरकार की डीज़ल नीति का अनुकरण करते हुए डीज़ल की कीमत पचास पैसे प्रति लीटर प्रति माह बढाने का निर्णय कर दिया। इसके बाद रेल बजट संसद में पेश होने से कुछ दिन पहले ही रेल किराये और माल भाड़े में भारी बढोतरी कर दी। रेल किराया सभी श्रेणियों के यात्रियों पर एक समान 14.2 प्रतिशत तथा माल भाड़ा 6.5 प्रतिशत बढा दिया। आश्चर्यजनक है कि एसी 1, 2, 3 तथा साधारण श्रेणी सभी पर बराबर बोझ डाल दिया। साधारण श्रेणी में यात्रा करने वाले तो अत्यंत गरीब लोग हैं जो स्लीपर क्लास की टिकट तक नहीं ले सकते उन पर भी भारी बोझ डाल दिया। मालभाड़ा 6.5 प्रतिशत बढाने से सामान की ढुलाई महंगी हो जाएगी जिससे सामान के दाम बढेंगे और महंगाई भी बढेगी। महंगाई की मार से त्रस्त जनता एक बार फ़िर अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर महंगाई भोगने को मजबूर हो गई है।

गौरतलब है कि जब यूपीए सरकार ने 2012 में रेल बजट से पहले रेल किराये बढाने की घोषणा की थी तब ऐलान होते ही भाजपा ने इस निर्णय की कड़ी आलोचना की थी तथा सोशल मीडिया पर मोदी ने 7 मार्च 2012 को ट्वीट किया था कि रेल बजट से ठीक पहले यूपीए सरकार ने संसद को बाईपास कर रेल किराया बढा दिया है। इसके खिलाफ़ प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। परंतु अब मोदी सरकार ने अपने उस एतराज को नज़रअंदाज करते हुए संसद को बाइपास कर यात्री किराये और माल भाड़े में वृद्धि कर दी। जब इस बढोत्तरी की आलोचना सभी विपक्षी राजनीतिक दलों तथा मीडिया द्वारा होने लगी तो रेलमंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि रेल किराया व माल भाड़ा बढाने का फैसला उनका नहीं है, यह निर्णय यूपीए सरकार ने किया था जो चुनाव आचार संहिता के कारण लागू नहीं हो सका था। उन्होंने तो यूपीए सरकार के निर्णय को ही लागू किया है। वास्तव में मोदी सरकार व रेलमंत्री इस तरह का हास्यास्पद जवाब देकर कांग्रेस द्वारा की जा रही आलोचना के तेवर को कुंठ करना चाहती है। यक्ष प्रश्न है कि मोदी व भाजपा ने यूपीए सरकार की नीतियों को जन विरोधी तथा देश हित विरोधी बताते हुए आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और जनता ने इन्हीं नीतियों के कारण यूपीए सरकार को बेदखल कर मोदी व भाजपा को सजा सौंपी थी। इसलिये यूपीए सरकार की नीतियों व निर्णयों को मोदी सरकार द्वारा लागू करने का औचित्य समझ नहीं आता। दूसरी तरफ केन्द्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि जनता को फैसला करना है कि उनको विश्वस्तरीय रेल चाहिए या जर्जर रेल भाजपा के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जरूरी होते हैं। रेल किराए में बढोतरी का फैसला भी वैसा ही है। रेल किराया व माल भाड़ा बढाने से लगभग 8 हज़ार करोड़ रुपए अतिरिक्त सालाना मिलेंगे। क्या इस राशि से लम्बित प्रोजेक्ट पूरे हो जाऐंगे और जर्जर रेल व्यवस्था सुधर जाएगी। रेलवे के एक अधिकारी के अनुसार बुनियादी ढांचे में सुधार के लिये पांच लाख करोड़ रुपए की जरुरत होगी। स्पष्ट है कि इसके लिये एक दीर्घकालीन योजना बनानी होगी तथा अतिरिक्त आवश्यक राजस्व जुटाने के लिए अन्य वैकल्पिक उपायों पर विचार करना होगा।

ध्यान देने वाली बात है कि यदि यूपीए सरकार द्वारा किए गए निर्णयों को ही मोदी सरकार ने लागू करना है तो यूपीए सरकार द्वारा गैर कानूनी जासूसी प्रकरण की जांच के लिए नियुक्त न्यायायिक आयोग और उसके द्वारा निर्मित साम्प्रयायिकता हिंसा बिल को क्यों निरस्त किया जा रहा है?

स्पष्ट है कि मोदी सरकार यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों को बदलने की बजट उन्हीं नीतियों पर चलेगी जिनकी मोदी ने कड़ी आलोचना की थी और जिनको जनता व देश के लिए घातक बताया था। इसका अर्थ है महंगाई पर लगाम लगाना मोदी सरकार के एजेंडा पर नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि अगले पांच महीने तक महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकेगा। केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने इससे भी आगे बढकर कहा कि जुलाई से दिसम्बर तक हर वर्ष महंगाई बढती ही है और खाद्य वस्तुओं की बढती कीमतों के लिए बिचौलियों द्वारा की जा रही जमाखोरी को जिम्मेदार ठहराया। स्पष्ट है कि मोदी सरकार यूपीए सरकार की तरह बढती महंगाई के लिए कोई न कोई बहाना तलाशकर जनता को मूर्ख बना रही है। जब से मोदी सरकार बनी है तब से महंगाई का बढना लगातार जारी है। इसके अतिरिक्त सरकार ने डीजल, रेल किराये तथा माल भाड़े में वृद्धि करने के बाद चीनी का आयात शुल्क 15 प्रतिशत से बढाकर 40 प्रतिशत करने से चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई है। इनके फलस्वरूप महंगाई का विकराल रूप धारण करने की आशंका है। मोदी सरकार द्वारा अच्छे दिन की अपेक्षा कहीं बुरे दिन तो नहीं लाए जा रहे हैं।